(e) Although there are no major labour problems like strike, lock-out etc. there are frequent instances of indiscipline affecting adversely productivity and maintenance of the plants.

New Price Index Series

*58. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to reply to Unstarred Question 2320 given in Rajya Sabha on 13th May, 1988 and state:

(a) whether the central trade unions were consulted before taking the decision regarding the introduction of the new price index series with 1982 as the base year; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) Yes, Sir.

(b) A national tripartite consultation, the second such consultation, was held on 6 October, 1988. At this consultation, the method for calculating the linking factor was discussed, besides details of the basis on which the 1982 base series has been drawn up.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*59. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले आयातित खाद्य तेल, गेहूं और चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इससे पूर्व मूल्यों में कब-कब और कितनी बार वृद्धि हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सुख राम) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान (1986 से 1988 तक) आयातित खाद्य तेलों, गेहूं तथा लेवी चीनी के मूल्यों में की गई वृद्धि नीचे दी गई है :—

वर्ष/तारीख	थोक में सप्लाई किये जाने वाले आयातित खाद्य तेल का मूल्य	15 कि० ग्रा० के टीनों में सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेल का मूल्य
आयातित खाद्य तेल		
1986	कोई वृद्धि नही की गई	कोई वृद्धि नहीं की गई
23-12-1987	9000 रु० प्रति मी० टन से 11000 रु० प्रति मी० टन	10500 रु० प्रति मी० टन से 12500 रु० प्रति मी० टन
1-9-1988	11000 रु० प्रति मी० टन से 13150 रु० प्रति मी० टन	12500 रु० प्रति मी० टन से 14500 रु० प्रति मी० टन

आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों तथा घरेलू बाजार में देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों के बीच के अंतर को कम करने और देशीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के कारण आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों को संशोधित किया गया ।

गेहूं

गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में 1986 से 1988 के दौरान निम्नलिखित संशोधन किया गया :—

वर्ष/तारीख	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि	समेकित आदिवासी विकास परियोजना के लिये गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि
1-2-1986	172 रु० प्रति क्विंटल से 190 रु० प्रति क्विंटल	कोई वृद्धि नहीं
1-5-1987	190 रु० प्रति क्विंटल से 195 रु० प्रति क्विंटल	125 रु० प्रति क्विंटल से 130 रु० प्रति क्विंटल
25-3-1988	195 रु० प्रति क्विंटल से 204 रु० प्रति क्विंटल	130 रु० प्रति क्विंटल से 139 रु० प्रति क्विंटल

गेहूं के निर्गम मूल्यों को वसूली मूल्यों में की गई वृद्धि को देते हुए तथा आदिवासी क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी व पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है ।

लेवी चीनी

वर्ष/तारीख	लेवी चीनी में वृद्धि
15-12-86	4.80 रु० प्रति कि० ग्रा० से 4.95 रु० प्रति कि० ग्रा०
1987	कोई वृद्धि नहीं
1-1-1988	4.85 रु० प्रति कि० ग्रा० से 5.10 रु० प्रति कि० ग्रा०

चीनी कारखानों द्वारा वर्षानुवर्ष अदा करने के लिये सरकार द्वारा नियत किये जाने वाले गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि होने और चीनी की परिवर्तन लागत में वृद्धि के फलस्वरूप लवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि की गई ।

Wilt Disease of Gauva Crop

*60. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Wilt disease has destroyed the Guava crop in vast areas of Andhra Pradesh and whether the soil-borne diseases also extend to other crops as well;

(b) whether such disease in Guava gardens has been noticed in other parts of the country; and

(c) if so, what steps Government propose to take to combat the menace?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) Wilt disease has affected the Guava crop in some districts of Andhra Pradesh. Guava wilt is not expected to affect other crops.

(b) Yes, Sir.

(c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.